

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 295]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2001/कार्तिक 11, 1923

No. 295]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2001/KARTIKA 11, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2001

विषय : यूरोपीय संघ (ईयू) और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

सं. 54/1/2001-डीजीएडी.—मै. दीपक नाइट्राइट लिमिटेड ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें यूरोपीय संघ और चीनी ताइपेई (ताइवान) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट के पाटन का आरोप लगाया गया है तथा उन्होंने पाटनरोधी जांच शुरु करने तथा पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

1. शामिल उत्पाद वर्तमान मामले में जांचाधीन उत्पाद यूरोपीय संघ और ताइवान के मूल का अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट एक आक्सीकारक एवं अवकारक एजेंट है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पावडर है जिसका उपयोग मुख्यतः

भेषजीय उद्योगों, रंजक उद्योगों, लुब्रिकेन्ट्स, निर्माण रसायनों, रबड़ गलाने वाले एजेंट हीट ट्रांसफर साल्ट, मांस प्रसंस्करण, वस्त्र इत्यादि उद्योगों में किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट के उत्पादन के लिए मुख्य कच्ची सामग्री अमोनिया है, जिसे उत्प्रेषक की उपस्थिति में उच्च ताप पर नाइट्रोस आक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।

2. सोडियम नाइट्राइट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के सीमाशुल्क उपशीर्ष संख्या 28.34.1001 के अंतर्गत वर्गीकृत है तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

3. घरेलू उद्योग का आधार देश में सोडियम नाइट्राइट का उत्पादन करने वाली निम्नलिखित कंपनियां हैं:-

- (क) दीपक नाइट्राइट लि०
- (ख) पंजाब कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०
- (ग) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०
- (घ) राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०

याचिकाकर्ता देश में सोडियम नाइट्राइट के भारतीय उत्पादन के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार उसके पास वर्तमान याचिका को दायर करने का आधार है।

4. शामिल देश इस जांच में शामिल देश/क्षेत्र यूरोपाय सच और ताइवान हैं (जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश/क्षेत्र कहा गया है)।

5. समान वस्तु याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु है। संबद्ध देशों से आयातित वस्तु को नियमों के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

6. पाटन और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य: याचिकाकर्ता ने तीसरे देशों को निर्यात किए गए सोडियम नाइट्राइट की कीमतों के आधार पर यूरोप में सामान्य मूल्य का दावा किया है। दावे का समर्थन उत्पादन लागत संबंधी अनुमानों के साथ किया गया है। ताइवान के मामले में सामान्य मूल्य का दावा उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है।

संबद्ध देश में सोडियम नाइट्राइट के सामान्य मूल्य के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

निर्यात कीमत याचिकाकर्ता ने डी जी सी आइ एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है। समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, स्वदेशी परिवहन और पत्तन हैंडलिंग तथा पत्तन प्रभारों के कारण निर्यात कीमत में से समायोजने का दावा किया गया है।

यंबद्ध देश से सोडियम नाइट्राइट की निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से काफी अधिक बनता है।

इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में जांचाधीन उत्पाद का सामान्य मूल्य उस कीमत से काफी अधिक है जिस पर भारत को इसका निर्यात किया गया है और यह कि ई यू और ताइवान के निर्यातक भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन कर रहे हैं।

7. **क्षति एवं कारणात्मक संबंध** घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक संकेतक जैसे आयात एवं उनका हिस्सा, निर्यात कीमत, उत्पादन, बिक्री, बिक्री कीमतों में गिरावट कीमत में कटौती कीमत में कमी/ह्रास लाभ/हानि कीमत इत्यादि सामूहिक और संचयी रूप से यह इंगित करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि विचाराधीन उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग की वास्तविक क्षति का कारण है।

8. **पाटनरोधी जांच की शुरुआत** पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों/क्षेत्र के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

9. **जांच की अवधि** वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 (12 महीने) तक की है।

10. **सूचना प्रस्तुत करना** संबद्ध देशों में निर्यातकों और भारत में संबद्ध समझे जाने वाले आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 को संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करें और अपने विचारों से अवगत कराएं। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संगत अनुरोध कर सकती है।

3428
3

11. समय सीमा वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में भेजी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी।
12. पाटनरोधी जांच एक समयबद्ध प्रक्रिया होने के कारण यदि निर्धारित समय के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है अथवा सूचना किसी भी रूप में अधूरी पाई जाती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को दर्ज कर सकता है।
13. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।
14. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

एल. बी. सप्ताश्रयि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2001

Subject : Initiation of anti-dumping investigations concerning import of Sodium Nitrite originating in or exported from European Union (EU) and Taiwan.

No. 54/1/2001-DGAD.— M/s. Deepak Nitrite Limited has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Sodium Nitrite originating in or exported from European Union and Chinese Taipei (Taiwan) and have requested for initiation of anti dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. Product Involved: The product under investigation in the present case is Sodium Nitrite originating in or exported from European Union and Taiwan. Sodium Nitrite is an oxidizing and reducing agent. It is a white crystalline powder mostly used in Pharmaceutical industries, Dye industries, as Lubricants, Construction chemicals, Rubber blowing agent, Heat transfer salts, and in meat processing, Textiles, etc. Major raw material for production of Sodium Nitrite is Ammonia, which is converted into Nitrous Oxide at high temperature in presence of catalyst.
2. Sodium Nitrite is classified under Customs sub-heading nos. 28.34.1001 of Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigations.
3. Domestic Industry Standing: The following companies are the producers of Sodium Nitrite in the country:-
 - (a) Deepak Nitrite Limited,
 - (b) Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
 - (c) National Fertilizers Limited,
 - (d) Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited,

3428-04/2001-2

The petitioner represent a major proportion of the Indian production of Sodium Nitrite in the country and thus have the standing to file the present petition.

4. Country(ies) Involved: The territory/country involved in the present investigations are European Union (EU) and Taiwan (referred to as subject country/territory hereinafter).
5. Like Article: The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from the subject countries. Goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles to the goods imported from the subject country/territory within the meaning of the Rules.
6. Dumping and Dumping Margin:

Normal Value: The petitioner has claimed normal value in EU on the basis of the prices at which Sodium Nitrite has been exported to third countries. The claim has been supplemented with the estimates of cost of production. Normal value in case of Taiwan has been claimed on the basis of the estimates of cost of production.

There is sufficient prime facie evidence with regard to normal value of Sodium Nitrite in the subject countries.

Export Price: The petitioner has claimed export price based on the data published by the DGCI&S, Calcutta. Adjustments have been claimed from the export price on account of Ocean Freight, Marine insurance, Commission, Inland Transportation and Port handling and port charges.

There is sufficient prime facie evidence with regard to export price of Sodium Nitrite from the subject countries.

Considering the normal value and export price, the dumping margins are significantly higher than the de-minimus limits.

There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the product under consideration in the subject countries is significantly higher than the price at which it has been exported to India, and that the exporters from EU and Taiwan are dumping the subject goods in India.

7. Injury and Causal Link: The various economic indicators relating to domestic industry such as imports and their share, decline in the export price, production, sales, selling prices, price undercutting, price suppression/depression, profit/loss etc. collectively and cumulatively, indicate that the domestic industry has suffered injury. There is sufficient prima facie evidence that the import of product under consideration have caused material injury to the domestic industry.

8. Initiation of Anti-Dumping Investigation: In view of the foregoing, the Designated Authority initiates anti-dumping investigations to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country/territory.
9. Period of Investigation: The period of investigation for the purpose of the present investigations is 1st April, 2000 to 31st March, 2001 (12 months).
10. Submission of Information: The exporters in the subject countries and the importers in India known to the concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Ministry of Commerce, Directorate General of Anti dumping and Allied Duties, Udyog Bhavan, New Delhi-110011. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.
11. Time Limit: Any information relating to the present investigations should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within forty days from the date of letter addressed to them separately.
12. Anti-dumping investigations being a time bound exercise, the Designated Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules supra, if no response is received within the time stipulated or the information is incomplete in any respect.
13. Inspection of Public File: In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
14. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

